

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हार्डिप में नहीं लिखें

३

न्यायिक सक्षिपता

न्यायालय की स्वयं स्वतंत्र जन सासन के

अन्य अंग संविधान समत तरीके से कार्य

न करे तो हस्तक्षेप करने या सक्षिपता

४

की को लक्ष्मि

विधि के शासन एवं संविधान की सर्वोच्चता

न्यायिक अंग है न्यायपालिका इतना प्रयोग

करती है

५

मूल हॉन्स

संविधान के वह अंग किन्हे किना संविधान की

६

मूल हॉन्स - ये संविधान के

मात्रा (लक्ष्म है) संविधान की भावना इनके बिना शून्य होती है

उद्घाटन के आरती, मातंग (१९५३) वेम्बरिवाड (१९५५)

मुख्य परीक्षा
म.प्र. लोक सेवा आयोग

नियम 10
के अन्तर्गत

H संपत्ति का अधिकार (अनु० 31-C)

संपत्ति का अधिकार को संविधान द्वारा पहले सुरक्षा प्रदान की थी जो कि अनु० 19 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार था किन्तु एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस मूल अधिकार से हटा दिया गया।

I समान नागरिक संहिता

(A) नीति निर्देशक तत्वों के अनु० 39 में वर्णित।

(B) साम्प्रदायिक देश में समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू।

(C) तीन तलाक़ मामलों के बाद से समान नागरिक संहिता का मुद्दा लीज हुआ है।

मुख्य परीक्षा
म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिए में नहीं लिखें

J

~~शाखायी अक्षरलेखी हेतु विशेष अधिकायी~~

~~संविधान के अनु० 350-15 में शाखायी~~

~~अक्षरलेखी हेतु विशेष अधिकायी का उपबंध दिया गया है~~

(7)

~~उद्देश्य शाखायी अक्षरलेखक मिले की रक्षा~~

K

(CAJ)

~~संविधान के अनु० 148-151 के अर्थ~~

~~के का की नियुक्ति योजना द्वारा शक्ति का वर्णन दिया गया है~~

~~मे भारत की बिलीय प्रणाली के निर्देश हैं~~

~~सब सरकार, सरकारी विभागों, लोक उपकरणों के लेखापत्री की लेखा पटीया का वापिले इन्हें रिपोर्ट लोपा क गया है~~

(7)

मुख्य परीक्षा
म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न क्रमांक

1

अखिल भारतीय सेवा

सांख्यिक अनु० 312 (राज्यीय)

सेवासूच-4 IAS, LPS, IPS

अधी- UPSC काम

2

बिलीय आपात (अनु० 360)

(1) जब देश में बिलीय संकट या मंदी का संकट हो।

(2) अ इस दौरान केन्द्र राज्य बिलीय संकट प्रभावित होते हैं।

3

कमिश्नरियों के वेतन-भाल में कटौती की जा सकती है।

4

अनिश्चित काल हेतु लगाया जा सकता है।

14

सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है।

17

लोकतांत्रिक विवेकीकरण

15

18

सला में सहभागिता व निर्णय लेने की शक्ति

19

का रूपांतरण स्तर तक विस्तार करना, विवेकीकरण सहलाता है।

20

सुवे संविधान संशोधन 1992 को इस दिशा में बेहतर उदम माना जा सकता है।

21

~~के.एम. पणिकर~~

22

~~संविधान सभा के~~

~~संविधान सभा के संविधान सभा में से~~

23

~~के.एम. पणिकर~~

24

कजल अली समिति (राज्य पुनर्गठन कायदा) 1955

के सदस्य में से एक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

गणराज्य लक्षार

(1) संसद में बार-बार छ मशीन हंडिंग
के आरोप।

(2) इलेक्ट्रिक डिवाइस होने के खराब होने
की समस्या।

(क)

(क)

मुख्य परीक्षा

ग.प्र. लोक सेवा आयोग

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

प्रश्न क्रमांक

B

स्थापना

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना

मजरा - Act 1986 काय हुई।

उद्देश्य

(A) पर्यावरण संबंधी मामलों का बोझ सुप्रीम कोर्ट से कम करना।

(ii) निम्न मामलों - (क) पर्यावरण प्रदूषण

(ख) पर्यावरण खराब

(ग) जैवविविधता

की सुनवाई।

(iii) पर्यावरण कानूनों को लागू करना

एवं सुरक्षा प्रदान करना।

(iv) अवमानना होने वाली इकाइयों को बंद करना।

(v) पर्यावरण संबंधी मामलों पर न्याय सौंपना।

सुप्रीम कोर्ट को लिखें

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

2

बिहार पत्रिका एडिटर आरक्षण

आवेदन का दिनांक

3/4

Page No. _____
Date _____

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

संविधान की रचना की महत्त्वपूर्ण

(1) संसद के

केन्द्र की महत्त्वपूर्ण विषय (समा, विदेश, संघ)

जमाया विषय (100)

(2) राज्य अनन्तर नहीं

केन्द्र राज्यों का नियंत्रण, ताम, जल संसाधन
आश्वासन वृद्धि द्वारा कर सकते हैं

(3) लचीला संविधान

संसद का साथ से जमाया डानूनों जो
विना राज्यों की सहमति संघोद्यन की
आवश्यक।

(4) राष्ट्रपाल की नियुक्ति

राष्ट्रपाल की नियुक्ति केन्द्र द्वारा किन्तु
राज्य को नियुक्ति करता है

(5) एकीकृत निर्वाचन व लक्ष्य मधीनकी

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग केन्द्र व राज्य

मुख्य परीक्षा

प्र.स. लोक सेवा आयोग

दोनों ही नियुक्ति कार्य सम्पन्न कराते ही
वही उच्च - उच्च व राज्य दोनों के
कर्मचारी की परीक्षा इतने ही

अतिरिक्त आतीष लेखक

उच्च स्तर नियुक्त होते हैं किन्तु सेवा
राज्यों में होते हैं। ये राज्य के
शासन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।

4

नीचे
में नह

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

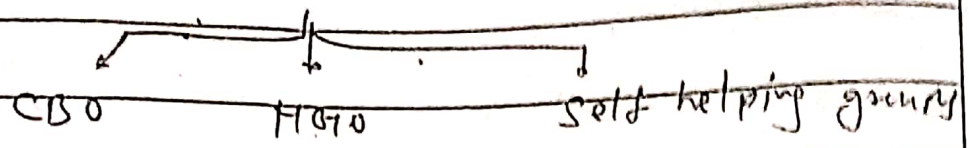
ग्र.प. लोक सेवा आयोग

स्वच्छिंद संगठन सरकारी संस्थानों

D

के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं

स्वच्छिंद संगठन (स्वच्छिंद से गठित)



समुदाय आधारित संगठन - जहाँ में

विकास कार्य, न केवल अब संरचना

बल्कि सामाजिक व आर्थिक सुधार में भी शासन के बड़े सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं

वही सरकारी, अर्थात् वंचित वर्ग, महिलाओं

रुब' अन्य सामाजिक उद्देश्यों हेतु निर्मित किए जाते हैं, तथा इन वर्गों की भावना

शासन तक पहुँचाते हैं। ये संगठन हैं

वंचित वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक

सहायता के कार्य में भी बड़े व्यय इत्यादि

में कार्यरत रहते हैं।

चाहे महामारी हो, या आपका इनका

कार्य शासन की जिम्मेदारी से आती है।

मुख्य परीक्षा

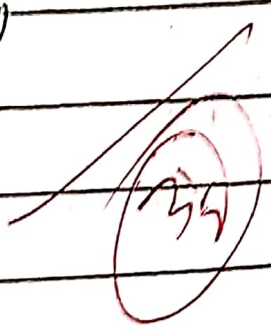
ग.प्र. लोक सेवा आयोग

इस प्रकार ~~किसी भी~~ ~~संज्ञा~~ ~~के~~ ~~अर्थ~~ ~~में~~ ~~सहभागिता~~ ~~के~~ ~~अर्थ~~ ~~में~~

पर हम कह सकते हैं कि ~~य~~ ~~संज्ञा~~ ~~के~~ ~~अर्थ~~ ~~में~~ ~~सहभागिता~~ ~~के~~ ~~अर्थ~~ ~~में~~

सरकारी संस्थानों के महत्वपूर्ण अंग

बन चुके हैं।



प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

जीवे हरीत
से नहीं फिरे

निवारक निलेख

E

संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निलेख का वर्णन किया गया है।

इसके अंतर्गत एक ऐसी शक्ति है जिससे किसी व्यक्ति को कपराय इन के द्वारा ही रोक जा सकता है।

निवारक निलेख दिया गया व्यक्ति को केवल उमराह जेल में निलेख दिया जाता है।

किन्तु उसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है और निलेख का कारण बताया जाता है।

इस अवस्था के कारण

(1) आतंकवाद एवं विनाशकारी गतिविधियों पर नियंत्रण।

(2) सामूहिक दंगों से दूर विरोधियों को निकल कराना।

(3) अल्पसंख्यकों पर नियंत्रण स्थापना।

मुख्य परीक्षा

स.प्र. लोक सेवा आयोग

(A) देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा।

(B) आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा हेतु।

उद्देश निम्नलिखित निदेशों द्वारा -

(1) TABA - 1987

(II) POTA

4

सं. प्र.
अ. प्र.

मुख्य परीक्षा

सं. प्र. लोक सेवा आयोग

न्यायिक पुनर्गठन (सन् 1957)

F

विधायिका के द्वारा निर्मित विधायी एवं
प्रशासन के कार्यों की संरक्षणात्मक
का परीक्षण करने का न्यायपालिका
का एक उपक्रम है।

इससे संसद द्वारा निर्मित अन्वय के
आधीन जो विधायी एवं विधायी संरक्षण
के साक्षात्कार का अतिरिक्त करने से
उन्हें न्यायपालिका शून्य घोषित कर देती है।

लाभ :-

(1) विधायिका एवं कार्यपालिका की
प्रभावशीलता बढ़ती है।

(2) सरकार का निरंकुश होने से रोड़ता।

(3) विधिका शासन सुनिश्चित रहती है।

(4) संविधान की शरीरगत की स्थापना
करती है।

उदाहरण :- न्यायपालिका ने सरकार को
असंविधानिक करार दिया।

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

मीडिया लोकतंत्र का चौथा

नीचे हाथों में नहीं लिखें

Z

स्तम्भ है।

मीडिया से तात्पर्य है (माध्यम) जो जनता एवं शासन के बीच संबंध का माध्यम होता है।

इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं यों कि यह शासन के अन्य तीनों स्तम्भों (जो जनता के प्रति उत्तरदायी बताता है)।

इसकी निम्न विधियाँ हैं-

(क) विधायिका एवं कार्यपालिका की जनता की ओर सावधानी बरतना।

(ख) शासन की अकुशलता पर तडक धरना।

(ग) शासन की गलत नीतियों की आलोचना करना।

(घ) सरकार की योजनाओं की समीक्षा करना एवं बाह-विचार करके तथ्यों की समीक्षा करना।

(ङ) शासन में आपत्तियों को उजागर करना।

गुरु पंक्तः

म. म. म. म. म. म. म. म. म. म.

आदि

॥

अथवा

अथवा

अथवा

अथवा

अथवा

अथवा

अथवा

॥

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा म.प्र. लोक सेवा आयोग

नाम लिखिए
मे नहीं लिखिए

7

नक्सलवाद
पश्चिम बंगाल के नक्सलारी गान में कौन से दशकों में
व्यापक शांतिपूर्ण रूप में समाप्त हुए थे

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए।
उपरोक्त नक्सलवाद की व्यापकता की

वृद्धि का कारण निम्नलिखित है -

(i) सरकारी उपेक्षा

नक्सलवाद समाप्त होने के कारण निम्नलिखित है।
कारण निम्नलिखित है। इनमें से सही विकल्प चुनिए।
समाप्त, असंस्थापित का आभाव रह है

(ii) संस्कृतियों पर चोट

स्थानीय समुदायों पर कानून अक्षयकारित
होना, उनके परम्परागत अधिकारों व
संस्कृतियों पर चोट दिमा गमना

(iii) शोषण

स्थानीय समुदायों का पहला
लाभकार, फिर अंततः भी उन शासन
के लक्ष्य बतल शोषण किया गया।

मुख्य परीक्षा

भू.प्र. लोक सेवा आयोग

वीथ रजि.
ब. मही ३३

(1) संघार साधना में अंतर्निहित

संघार के उपादान में से लोग बाहरी
दुःखों से शासन से जुड़ नहीं पाते।

(2) बाह्य दुःखों की शक्ति

चीन जैसे देशों का अर्थव्यवस्था, हथियार
व बिल पोषण।

(3) प्रशासनिक सेवा का निम्न स्तर

सर्वान्तर ज्ञान पश्चात्, अनुभव, क्षमता

(4) सिन्धु धारा

उपादान नसकवाही वा प्रपण से
प्रशासनिक से राज अपने सन्त दुःखों
है दु शासन के निम्न स्तर मानते है

प्रश्न

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

संबंधानि संस्थापन (महिला)

नीचे हरियर में नहीं लिखें

1

(1) विधि के समान समानता (अनु 14)
पुरुष व स्त्री में कोई विभेद नहीं

(11) अवसर की समानता (अनु 16)
आसानी से समान अवसर तथा
विधि साधनी

(111) अनु 23 - महिलाओं का कुर्बियार रोक
रखा

(112) समान वेतन सुनिश्चित करना - अनु 32

(113) सशक्ति पौरान लोक सहायता का
अधिकार - अनु 41

(114) समान नागरिक संहिता अनु 34

(115) अनु 31-16 मूल कर्तव्य
महिलाओं की गरिमा को
घात करने वाली व्यवस्था का खराब

(116) 243-D - महिलाओं को उच्च आरक्षण

किसी हकीकत में नहीं लिखें

मुख्य परीक्षा

सम लोक सेवा आयोग

सम लोक सेवा आयोग महि. दू. ७०

प्रश्न क्रमांक

2

लाभ - 24-सितम्बर - 2011

उद्देश्य - गुणवत्ता पूर्ण सेवा समग्र

समवर्द्धता

शिक्षागत निगरान

सामर्थ्य

(1) उच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवा

(2) समग्र पर सेवा सहान चलाना

(3) त्वरित शिक्षागत निवारण लागू

(4) सेवाओं को डिजिटल माध्यम से प्रदान

(5) सेवाओं में पारदर्शिता

4

(6) कम व्यय एवं कम समय में सेवा

(7) सेवा क्षमताओं में हलिया

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

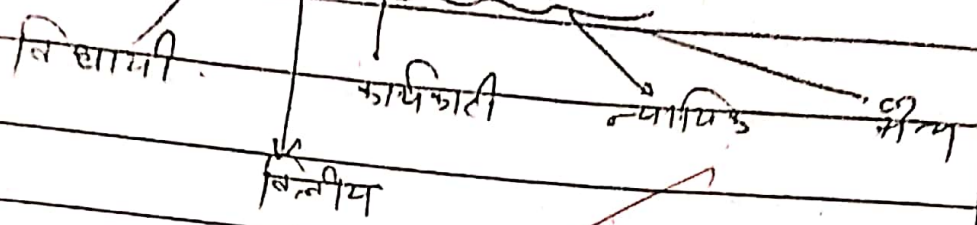
ग.प्र. लोक सेवा आयोग

कोचे कक्षा
में परीक्षा

3 (A)

~~संघसंरचना~~

राष्ट्रपति की शक्तियाँ



(i) विधायी -> (1) अस्थापित जाती कला (अनु 125)
(ii)

संसद सह प्राप्त कला
(iii) राष्ट्रपति का अधिकार

(iv) विधेयको को सहायता, स्वीकृति व पुनर्निचार हेतु लेना।

~~(v) राज्य विधेयको पर विचार कला~~

कार्यकारी

(1) नियुक्तियाँ - प्रधानमंत्री
अन्तर मंत्री
सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट
के न्यायाधीश
~~जुज, मुख्य न्यायाधीश व प्रापु~~
अन्त

मुख्य परीक्षा

स.प्र. लोक सेवा आयोग

(11) अग्रतः प्रगामात्र, काय राष्ट्रपति की

नाम से संभाषित

(12) लक्ष्मीप, तादरागत हकी . आधुनात

का प्रशासन ।

(13) अनुसूचित जेठ की योजना ।

(14) आयोगों की प्रकृति के अर्थों की परिभाषा

(I.C., S.A., O.B.C., महिला आयोग)

विलीप

(15) धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के ही प्रस्तुत होते हैं

(16) आउटफिटिंग विधि राष्ट्रपति का अधिकार होता है

(17) जो भी अनुदान मांगे राष्ट्रपति की अनुमति बिना नहीं रहती कानी

न्यायिक

(18) न्यायाधीशों की नियुक्ति (सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट)

(19) न्यायाधीशों की शक्तियाँ

नीचे हरीत में नहीं कि

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

न
क्रं

(11) समाप्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के ही

नाम से सम्पन्न।

(12) लक्ष्मीप, पादरानगा बेली, आरुणा

का प्रशासन।

(13) अनुसूचित वर्ग की शोषणा।

(14) आयोगों के अन्तर्गत की नियुक्ति

(डा. डा. वरत, महिला आयोग)

बिस्मिल

(15) इन विशेषण राष्ट्रपति की सहमति से ही हस्तगत होते हैं।

(16) आसक्ति वा विधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है।

(17) यदि जी अनुदान माँगा राष्ट्रपति की अनुमति बिना नहीं रहनी जानी।

न्यायिक

(18) न्यायाधीशों की नियुक्ति (मुन्शीम डोह, इल डोह)

(19) न्यायाधीशों की शक्तियाँ

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिए में नहीं लिखें

सैन्य

(1) तीन सैन्यो का सेनापति

(2) केहि माशाल सभाल इति का अर्थिकार

क्या राष्ट्रपति स्वर लोप है ?

मह सत्य है डि भारत मे राष्ट्रपतिको नाममात्र ही है। राष्ट्रपति नाममात्र ही कार्यपालिका है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है किन्तु निम्न मामले मे उसे बरबित ही शक्तियाँ हैं-

(1) विधेयक पुन विचार हेतु लौटाना।

(2) बहुमत रखने पर सरकार को बरबित डालना।

(3) प्रधानमंत्री से प्रशासनिक व विधायिका के विधायन प्रणाली की लानचाली माँगना।

(4) प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी न हो तो वह एकविधिक का सम्भोग कर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

(5) स्पष्ट बहुमत सभल न होने पर डिमी हल को सरकार बनाने हेतु माँगना समाप्त

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

यस तकार राष्ट्रपति को पत्र लिखे
शक्तियों प्राप्त हैं। शायद ही उसका पद
संबन्धित है और शासन में उसका स्थान
अल्प है।

निष्कर्ष: ज्यादातर मामलों में नियम के
अधीन परिसर की परामर्श पर निर्भर है
किन्तु स्वतंत्र शक्तियों के होते हुए
रबर स्टॉप का नाम देना तक संभव नहीं
होगा।

10

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

स्वशासन पद्धति का विकास

भारत में प्राचीन काल में ही स्वशासन के गुण विद्यमान रहे जैसे

अधिशाल - (क) 6 समितियों नगरों का हस्तचन करती हैं।

(ख) ग्रामीण - ग्राम का विषय प्रति विषयों का स्वशासन

इतर गैर अशिलेख
चाल डाली

- (क) उत्तर - स्वशासन का वर्गन
- (ख) महासभा - संसामान्य की सभा
- (ग) नगरम - अग्रहणों की सभा
- (घ) नगरम - स्वशासन की सभा

व्यापारिक - स्वशासन का प्रयोग
भारत में स्वशासन
के आधुनिक प्रयोग
पहला नगर निगम - महास
का।

मुख्य पराक्षा
ग.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न क्रमांक

प्रश्न क्रमांक	प्रश्न
<input type="checkbox"/>	बलवंत राय गेहला समिति (1957)
<input type="checkbox"/>	द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव
<input type="checkbox"/>	ग्राम मंडल जिला स्तर पर
<input type="checkbox"/>	अशोक गेहला समिति (1978)
<input checked="" type="checkbox"/>	द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव
<input checked="" type="checkbox"/>	मंडल स्तर जिला स्तर
<input checked="" type="checkbox"/>	सिंधली समिति (1986)
<input type="checkbox"/>	पंचायती राज का संवैधानिक ढांचा की प्रौढ
<input type="checkbox"/>	73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992
<input type="checkbox"/>	29-अप्रैल - 1993 से लागू
<input type="checkbox"/>	भाग-9, 243-293 (0) तक
<input type="checkbox"/>	243-अ ग्राम सभा
<input type="checkbox"/>	243-ब आरक्षण
<input type="checkbox"/>	293 I खजाने वित्त भाग
<input type="checkbox"/>	293 (3) राज्य निर्वाचित भाग

प्रश्नपत्र (for civil services)
 भा.प्र. सेवा आयोग
 293 (क) राज्य लक्ष्य कक्षा

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

भीचे हाशिए
में नहीं लिखें

74 (11A) (1993)

नागरीय विकास की स्थापना, एवं शक्ति
प्रदाय

माला

(1) लोकतंत्र को मूल रूप स्थापन किया गया

(2) सन्तानों सहभागिता एवं निर्माण
की शक्ति का ज्ञान तक विस्तार

(3) लक्ष्मी वर्गों की सहभागिता
युनिश्चित।

(4) ग्रामीण व जिला स्तर पर समाज का
जिला स्तर पर समाज का

(5) ग्रामीण विकास युनिश्चित।

(6) योजनाओं की सफलता एवं
समावेशन को साकार किया।

(7) ग्राम स्तर तक आवश्यकताओं
की समुदाय

96

मुख्य परीक्षा

नीचे छात्रों
में नहीं लिखें

म.प्र. लोक सेवा आयोग

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

साबधान- अनुच्छेद (25-28)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्मों को समानता दी गई है। शासन धर्म से तटस्थ रहता है।

धार्मिक स्वतंत्रता के अर्थों में साबधान निम्न है-

(1) अंतःकरण की सुनने व धर्म मानने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-25)

सर्वे धर्मों को अपनी शक्ति के धर्म की मानने की स्वतंत्रता है।

उदाहरण के लिए ->

(1) सिक्खों को अपना धर्म मानने का अधिकार है। अतः उन्हें स्वतंत्रता दी गई।

मुख्य परीक्षा

ग.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न क्रमांक

(11) धार्मिक कार्य करने एवं उपान्चरण

की आवश्यकता (अनु 26)

सिद्ध करके को अपने धर्म के अनुसार

आन्चण करने एवं धार्मिक कार्यों

के प्रवर्धन का अधिकार होगा।

किन्तु धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(12) धार्मिक कर्म

करों का प्रयोग धर्म के पोषण

पर नहीं किया जाएगा

(अनु 27)

आयति कर से प्राप्त राशि का

प्रयोग किसी धर्म विशेष के

पोषण में नहीं किया जाएगा

(13) अनु 28

राज्य निधि से व्यय

पोषित किसी संस्थान

में धार्मिक शिवा प्रवर्धन नहीं

मुख्य परीक्षा

ग.प्र. लोक सेवा आयोग

धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के कारण

(17) भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।

(18) सभी समानता के सिद्धान्त।

(19) तल्लेड वर्ग की कल्याण।
युनैनिमी

(20) धर्मनिरपेक्ष भागले।

(21) धार्मिक स्वतंत्रता।

(22) धर्म का धारित हिस्सा।

(23) वाटकेड लेडु धर्मो का तु ली कथा

उपाय

(1) संबुलर रिजिमा पल्लति।

(2) एका धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करण

(3) सुल्लेड कु ल डी नीति।

(4) अतिवृत्ता के सिद्धान्त

(5) राष्ट्र सभी परि का सिद्धान्त।